डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

2025
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 1 नवम्बर, 2025, डिस्पेच दिनांक 1 नवम्बर, 2025

| वर्ष 69 | अंक 11 | भोपाल | 1 नवम्बर, 2025 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

किसान हमारी अर्थव्यवस्था की हैं रीढ़ : मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश का अन्नदाता अब बन रहा है ऊर्जादाता

किसानों का कल्याण सर्वोपरि, किसान हित में करेंगे सभी प्रयास

सूखे खेत को पानी मिल जाये तो फसल हो जाती है सोना

हम हर खेत तक पहुंचायेंगे पानी

किसानों की खुशहाली ही हमारे विकास का है मुख्य आधार

मुख्यमंत्री ने सोलर पंप स्थापना के लिये की किसानों को 90 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा

विद्युत पंप से एक स्टेप अधिक पॉवर केपिसिटी का दिया जायेगा सोलर पंप

सोयाबीन पर भावांतर भुगतान के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री निवास में हुआ किसान आभार सम्मेलन

भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के 3 हजार से अधिक किसान हुए शामिल

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारे किसान भाई ही मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार का हर निर्णय किसानों के कल्याण को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। किसानो की भलाई के लिए हमारी सरकार हर जरूरी कदम उठायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर संभव तरीके से किसानों की आय बढ़ाकर उनकी माली हालत मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। भावांतर योजना किसानों को खुले बाजार में फसलों की कीमतों के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा देती है। यह योजना किसान हित में सरकार की एक बड़ी पहल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को मुख्यमंत्री निवास परिसर में 'सोयाबीन पर भावांतर भुगतान के उपलक्ष्य में' आयोजित किसान आभार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सूखे खेत को अगर पानी दे दिया जाये, तो फसल सोना हो जाती है, हम प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुंचायेंगे। मध्यप्रदेश के अन्नदाता अब ऊर्जादाता बन रहे हैं। किसान भाई अपने खेतों में सोलर पंप जरूर लगाएं। सोलर पंप लगाने से बिजली के अस्थाई कनेक्शन के खर्च से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सोलर पॉवर पंप स्थापना के लिये किसानों को अब 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। पहले 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को विद्युत पंप से एक स्टेप अधिक पॉवर केपिसिटी का सोलर पॉवर पंप दिया जायेगा अर्थात् 3 HP वाले किसान को 5 HP का सोलर पॉवर पंप और 5 HP वाले किसान को 7.5 HP का सोलर पॉवर पंप दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने किसान आभार सम्मेलन में पारम्परिक वेशभूषा में सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले सभी कलाकारों को 5-5 हजार रूपए देने की घोषणा भी की। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलन तथा भगवान हलधर बलराम एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर सम्मेलन की विधिवत् शुरूआत की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान भाइयों की मेहनत से ही प्रदेश की जीडीपी में कृषि 39 प्रतिशत से अधिक का योगदान देती है। किसान भाई सच्चे अर्थों में मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, फलों और सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन के उत्पादन के मामले में भी हम कम नहीं हैं। संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक और धनिया उत्पादन में मध्यप्रदेश नंबर वन है। मटर, प्याज, मिर्च, अमरूद उत्पादन में दूसरे तथा फूल, औषधीय एवं सुंगधित पौधों के मामले में तीसरे स्थान पर मध्यप्रदेश है। उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश सोयाबीन स्टेट, मिलेट्स स्टेट, मसाला स्टेट, लहसुन स्टेट और संतरा स्टेट के रूप में प्रसिद्ध होकर देश का फूड बास्केट कहलाने लगा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खेती-किसानी के लिए जल अमृततुल्य होता है। इसीलिए जल-संरक्षण के हर जरूरी उपाय कर जल अवश्य बचायें। हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी अंचलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3 बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं पर काम प्रारंभ किया है। राजस्थान के साथ पार्वती-काली सिंध-चंबल (पीकेसी) नदी जोड़ो से बुंदेलखंड और चंबल, उत्तरप्रदेश के साथ केन-बेतवा से बुंदेलखंड और महाराष्ट्र के साथ ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना से हम प्रदेश के सभी अंचलों में सिंचाई की स्थाई सुविधा उपलब्ध कराने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान धरती माता के वास्तविक पुत्र हैं। मध्यप्रदेश नदियों का मायका है। प्रदेश में 250 से अधिक नदियां निकलती हैं। मां नर्मदा प्रदेश के किसानों के लिए वरदान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को अनुदान पर सोलर पंप प्रदान कर रही है। किसान को 90 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप दे रहे हैं। किसानों को 32 लाख सोलर पंप दिए जा रहे हैं। किसान 5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप लगाएं। बिजली का खर्च बढ़ाएं और अतिरिक्त बिजली सरकार को बेचें। हमारी सरकार आने पर प्रदेश में अब 52 लाख हेक्टेयर रकबा सिंचित हुआ है। नदी जोड़ो योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों की फसल को पानी मिल जाए, फसल सोने की हो जाती है। राज्य सरकार ने सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य रखा है। किसानों को उनकी फसल का समुचित दाम मिले, इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी स्थापित की जा रही हैं, जिससे अधिक उत्पादन होने पर किसान भाइयों को फसल फेकनी न पड़े।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पहले फसल का सीजन निकल जाने पर मुआवजे की राशि भेजी जाती थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने सोयाबीन की फसल काटने से पहले ही राशि बांटना शुरू कर दिया है। किसानों की परेशानी किसान का बेटा ही समझ सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों के लिए भावांतर योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसान भाई पवित्र मन से दूसरों का पेट भरने के लिए अन्न उगाते हैं। पुरानी सरकारों ने मां नर्मदा के जल का उपयोग नहीं किया। आज वही नर्मदा सिंचाई, पेयजल और उद्योगों को पानी उपलब्ध कराती है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने दर्ज किया अब तक का सर्वोच्च वित्तीय प्रदर्शन; रु.750 करोड़ का शुद्ध लाभ

नई दिल्ली, देश में सहकारिता आंदोलन को वित्तीय शक्ति प्रदान करने वाली शीर्ष सरकारी संस्था राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने वित्त वर्ष 2024–25 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। निगम ने इस अवधि में रु.750 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो उसके इतिहास में एक नया कीर्तिमान है।

रिकॉर्ड स्तर की वित्तीय उपलब्धियाँ

सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत एनसीडीसी ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान रु.1,30,377.60 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की, जबकि रु.95,175.71 करोड़ की राशि विभिन्न सहकारी संस्थाओं को वितरित की गई।

इन सहकारिताओं में कृषि, डेयरी, मत्स्य, प्रसंस्करण, विपणन, आवास, स्वास्थ्य तथा सेवा क्षेत्र की संस्थाएँ शामिल हैं।

इस अवधि के दौरान 2,76,760 सहकारी समितियों और 1.27 करोड़ सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला, जिससे ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सहकारिता की पहुँच और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

राज्यों में व्यापक विस्तार और जमीनी सहयोग

एनसीडीसी की गतिविधियाँ देश के 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैली हुई हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य इसके सबसे सक्रिय साझेदार हैं।राज्य स्तरीय संघों, जिला सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के साथ निगम का सहयोगात्मक मॉडल ग्रामीण स्तर पर लक्षित वित्तीय हस्तक्षेपों को सफल बना रहा है।

वित्तीय मजबूती और उत्कृष्ट प्रबंधन

1963 में स्थापना के बाद से एनसीडीसी ने निरंतर लाभप्रदता का रिकॉर्ड कायम रखा है। वित्त वर्ष 2024–25 में निगम ने यह परंपरा जारी रखते हुए शून्य शुद्ध एनपीए (NPA) और 99.75% की ऋण वसूली दर हासिल की।

31 मार्च 2025 तक एनसीडीसी का कुल संचयी वितरण रु.4,08,376.68 करोड़ तक पहुँच गया।

वर्ष 2015–16 में जहाँ वितरण केवल रु.7,118 करोड़ था, वहीं 2024–25 में यह बढ़कर रु.95,175.71 करोड़ हो गया — जो लगभग 33% की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर (CAGR) को दर्शाता है।

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 57% की वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि देश में सहकारी वित्तपोषण की मांग तेज़ी से बढ़ रही है।

सरकारी पहलों के अनुरूप भूमिका

एनसीडीसी ने केंद्र सरकार की प्रमुख सहकारी पहलों को प्रभावी रूप से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाई है।इसमें शामिल हैं —

- 10,000 किसान उत्पादक संगठन (FPOs) के गठन एवं प्रोत्साहन,
- PACS के कंप्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण,
- सहकारी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन,
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता,
- तथा महिला और जनजातीय सहकारिताओं को विशेष ऋण सहायता।

निगम ने आनंद मॉडल पर आधारित डेयरी यूनियनों, निर्यात-उन्मुख विपणन सहकारिताओं और ग्रामीण महिला स्वावलंबन समूहों के लिए भी विशेष वित्तीय योजनाएँ चलाई हैं।

भविष्य की दिशा: सतत और डिजिटल सहकारिता

एनसीडीसी ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए रु.80,000 करोड़ के वितरण लक्ष्य का निर्धारण किया है।

आने वाले समय में निगम का फोकस निम्न बिंदुओं पर रहेगा —

- गुणवत्तापूर्ण ऋण प्रबंधन,
- डिजिटल निगरानी एवं पारदर्शिता,
- सदस्य सहकारिताओं की क्षमता निर्माण,
- तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप निवेश।

नए क्षेत्रों में निगम नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर, कृषि लॉजिस्टिक्स, और जलवायु-संवेदनशील अवसंरचना परियोजनाओं को प्राथमिकता देने जा रहा है।

"सहकार से समृद्धि" की दिशा में दृढ़ कदम

सरकार के "सहकार से समृद्धि" अभियान के अनुरूप एनसीडीसी अब स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन, शिक्षा और सेवा क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की भूमिका को और मजबूत करने पर कार्य कर रहा है।निगम का लक्ष्य न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना है, बल्कि सहकारी संस्थाओं को सलाह, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग देकर आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाना भी है।

एनसीडीसी का यह प्रदर्शन न केवल सहकारिता आंदोलन की सशक्त होती दिशा का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि यदि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और नवाचार एक साथ हों, तो सहकारी मॉडल देश की अर्थव्यवस्था के लिए विकास का स्थायी स्तंभ बन सकता है।

अब बिना इंटरनेट के करें पैसे का लेन-देन : आरबीआई ने लॉन्च किया ऑफलाइन 'डिजी रुपी'

मुंबई : भारत के डिजिटल वित्तीय ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऑफलाइन 'डिजी रुपी' प्रणाली की शुरुआत की है।यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी धन का लेन-देन (Money Transfer) करने की अनुमति देगी।

घोषणा फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान मुंबई में की गई — यह देश में वित्तीय समावेशन और डिजिटल नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

क्या है ऑफलाइन डिजी रुपी

'डिजी रुपी' भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई एक डिजिटल मुद्रा (Digital Currency) है, जिसका मूल्य पारंपरिक रुपये के समान है।यह इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध होती है और वॉलेट-टू-वॉलेट धन हस्तांतरण की सुविधा देती है — यानी इसके लिए बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती।उपयोगकर्ता इसे डिजिटल वॉलेट्स में संग्रहीत कर सकते हैं और UPI की तरह QR कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। इससे नकद रहित और त्वरित भुगतान को नई दिशा मिलेगी।

दो मोड में होगा ऑफलाइन भुगतान

आरबीआई द्वारा शुरू किया गया ऑफलाइन डिजी रुपी दो प्रमुख तकनीकी मोड्स पर कार्य करेगा —

1. टेलीकॉम-सहायता प्राप्त प्रणाली (Telecom-assisted mode):

यह प्रणाली सीमित नेटवर्क में भी

काम करती है। इसमें न्यूनतम सिग्नल की आवश्यकता होती है, जिससे कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी भुगतान संभव हो सकेगा।

2.एनएफसी (Near Field Com munication) आधारित प्रणाली:

इस तकनीक में उपयोगकर्ता अपने मोबाइल फोन को सिर्फ टैप करके भुगतान कर सकते हैं।

इससे इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के बिना भी व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति-से-व्यवसाय (P2M) भुगतान संभव होगा।

भागीदार बैंक और वॉलेट सेवाएँ

इस सेवा के लिए कई प्रमुख बैंक डिजी रुपी वॉलेट्स की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं —भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, कर्नाटक बैंक और इंडियन बैंक।

इन बैंकों के मोबाइल एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध हैं।

वॉलेट्स में उपयोगकर्ताओं को धन प्रबंधन, न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने, और मोबाइल खो जाने पर वॉलेट पुनर्प्राप्त करने जैसी सुविधाएँ भी दी जाएँगी।

ग्रामीण भारत को मिलेगी बड़ी राहत

ऑफलाइन डिजी रुपी प्रणाली से सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को मिलने की उम्मीद है, जहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी अक्सर कमजोर रहती है।इस तकनीक से किसान, छोटे दुकानदार, स्वयं सहायता समूह (SHGs) और ग्रामीण उपभोक्ता बिना इंटरनेट के भी आसानी से भुगतान, खरीद-बिक्री और धन स्थानांतरण कर सकेंगे।यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

डिजिटल समावेशन की दिशा में बड़ा कदम

आरबीआई की यह पहल देश को डिजिटल वित्तीय समावेशन की दिशा में एक नया आयाम देने वाली है।ऑफलाइन डिजी रुपी से डिजिटल लेन-देन अब अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और सुलभ बनेंगे, जिससे हर नागरिक, चाहे वह किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकेगा।आरबीआई ने कहा है कि भविष्य में डिजी रुपी को स्मार्ट कार्ड्स, वियरेबल्स (Wearables) और ऑफलाइन पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेज़ तक विस्तार देने की योजना है, जिससे यह तकनीक और भी व्यापक हो जाएगी।

ऑफलाइन डिजी रुपी की शुरुआत से भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक नई दिशा तय की है।यह कदम न केवल वित्तीय समावेशन को गहरा करेगा, बल्कि डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक मजबूत आधारशिला रखेगा।आरबीआई की यह पहल भारत को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रही है, जहाँ हर लेन-देन — चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन — सुरक्षित, त्वरित और पारदर्शी होगा।

सहकारिता से आत्मनिर्भरता की ओर बेटियाँ : नौगांव में सहकारिता इंटर्नशिप कार्यक्रम का सफल समापन

नौगांव (छतरपुर): मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में युवाओं की सहभागिता एवं व्यावहारिक ज्ञानवृद्धि के उद्देश्य से 'सहकारिता इंटर्नशिप कार्यक्रम' का सफल आयोजन किया गया।इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय बापू महाविद्यालय, नौगांव की छात्राओं को प्रशिक्षण उपरांत प्रमाणपत्र प्रदान कर कार्यक्रम का समापन किया गया।

युवाओं को सहकारिता से जोड़ने की पहल

यह विशेष इंटर्नशिप मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर प्रारंभ की गई थी।कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं—विशेषकर छात्राओं—को सहकारिता की अवधारणाओं, संगठनात्मक ढांचे और प्रबंधन कौशल से जोड़ना तथा उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करना है।

डेढ़ माह चला प्रशिक्षण:सैद्धांतिक और व्यावहारिक सीख का संगम

कार्यक्रम के तहत बापू डिग्री कॉलेज, नौगांव की 10 चयनित छात्राओं को 1 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव में प्रशिक्षण दिया गया।प्रशिक्षण अवधि के दौरान छात्राओं को सहकारिता की मूल अवधारणा, सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली, संगठनात्मक संरचना और प्रशिक्षण विधियों की गहन जानकारी दी गई।प्रशिक्षण केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं रहा — छात्राओं ने व्यावहारिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की।प्रत्येक छात्रा को एक सहकारी संस्था और दो विद्यालयों में जाकर सहकारिता विषय पर प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी दी गई, जिसे सभी ने सफलता से पूरा किया।

नेतृत्व, संगठन प्रबंधन और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य शिरीष पुरोहित ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं, विशेषकर छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, संगठन प्रबंधन कौशल और स्वावलंबन की भावना को विकसित करना है।उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण छात्राओं के लिए भविष्य में शिक्षक, प्रशिक्षक या सहकारी क्षेत्र में नेतृत्व अवसरों के रूप में नई संभावनाएँ खोलेगा।

छात्राओं को मिला सम्मान और प्रोत्साहन

समापन समारोह में छात्राओं को इंटर्नशिप प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।साथ ही प्रत्येक छात्रा को रु.7,500 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।छात्राओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण उनके लिए जीवन में नई दिशा और आत्मविश्वास लेकर आया है।उन्होंने न केवल सहकारिता के सिद्धांतों को सीखा, बल्कि उनके व्यावहारिक उपयोग को भी अनुभव किया।

महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की ओर

यह इंटर्नशिप न केवल छात्राओं के लिए सीख का अवसर बनी, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक प्रेरक पहल के रूप में सामने आई।

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरंतर रखे जाने का निर्णय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरंतर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च, 2026 और रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2026 नियत की गयी है।

योजनान्तर्गत खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित तिथि (ड्यू डेट) तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा 3 लाख रूपये तक के दिये गये अल्पावधि फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा सभी किसानों के लिए 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा। वर्तमान वर्ष में 23 हजार करोड़ रूपये वितरण का लक्ष्य रखा गया हैं।

प्रतिस्पर्धात्मक दौर में शाखा प्रबंधक उत्कृष्ट कार्य करें

अपेक्स बैंक के शाखा प्रबंधकों की बैठक

भोपाल : अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष, 2025 के दौरान अपेक्स बैंक के प्रदेश के शाखा प्रबंधकों की बैठक को अपेक्स बैंक समन्वय भवन स्थित सभागार में हुई। इस अवसर पर बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने शाखाओं द्वारा की गई अमानत संग्रहण, ऋण वितरण, वसूली एवं बीमा योजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देशित किया कि प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने आप को बेहतर साबित करने की दिशा में सभी अधिकारी पूरी ईमानदारी एवं लगन से अपने उत्तरदायित्वों का निवर्हन करें। उन्होंने 22 अक्टूबर तक चलाये गये बचत माह के दौरान व्यक्तिगत हितग्राहियों को विभिन्न प्रयोजनों यथा - आवास एवं अचल सम्पत्ति के बंधक पर ऋण पर 8.00 प्रतिशत, वाहन ऋण 8.50 प्रतिशत एवं आवास ऋण 9.00 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराने के प्रयास किए।

श्री गुप्ता ने बैंक की शाखाओं के माध्यम से माईक्रो एटीएम एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की अधिक से अधिक जानकारी अपने ग्राहकों एवं आमजन तक पहुँचाकर लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये प्रेरित करने तथा एन.पी.ए. प्रकरणों के निराकरण करने और केन्द्र सरकार की ''स्वच्छता पखवाड़ा'' योजना का सतत् आयोजन करने के निर्देश भी दिये।

आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का लक्ष्य प्राप्त करने राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के माध्यम से विश्व में एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पाद अपनाकर और भारतीय उद्यमियों और कारीगरों का समर्थन कर हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को समन्वय भवन भोपाल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से भारत में व्यापार व्यवसाय समृद्ध रहा है। अनुशासित जीवन पद्धति जियो और जीने दो के विचार का अनुसरण करने के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज सदैव पुष्पित पल्लवति होता रहा है। समाज में विद्यमान धर्मादा की परम्परा से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जनकल्याण गतिविधियों का संचालन होता था। पिछली सरकारों की लाइसेंस, कोटा, परमिट जैसी नीतियों से देश की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और समाज द्वारा संचालित व्यवस्थाओं में भी शासकीय हस्तक्षेप के दुष्परिणाम सामने आने लगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपई ने अपने अतीत को गौरव के साथ देखने की दृष्टि दी और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारतीय बौद्धिक सामर्थ्य को विश्व में स्थापित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और पहल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख और आर्थिक सामर्थय स्थापित हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी किसानों के हितैषी होने के साथ ही मजदूरों, व्यापारियों सहित सभी वर्गों के हित चिंतक हैं। उनके मार्गदर्शन में व्यापार-व्यवसाय और कर व्यवस्था में लागू सरल और पारदर्शी नीतियों ने आम आदमी के जीवन को सुगम बनाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में उद्योग तथा निवेश गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए जारी गतिविधियों से स्वदेशी को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आगामी दिनों में आ रहे त्यौहारों में स्वदेशी सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए उपस्थित जनसमुदाय को प्रेरित किया।

इस अवसर पर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई गई। इसमें नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करने, आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाने, घर,काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देने और गांव, किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई गई। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए नई पीढ़ी को पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति-अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करने तथा देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता देने का संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम को सांसद व राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरूण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल, सांसद श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री भगवान दास सबनानी ने भी संबोधित किया।

दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है : मंत्री श्री वर्मा

भोपाल : राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दुग्ध उत्पादकों के कल्याण के लिए कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनसे किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि हो रही है। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने सीहोर जिले के ग्राम टिटोरा में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित टिटोरा के बोनस वितरण समारोह में यह बात कही। उन्होंने समिति के सदस्यों को बोनस का वितरण और अधिक दुग्ध संकलन करने वाले प्रदायकों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और समिति के सदस्य उपस्थित थे।

कोदो-कुटकी का पहली बार उपार्जन किये जाने का निर्णय

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रमुख कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों के कृषकों से पहली बार कोदो-कुटकी उपार्जन का किये जाने का निर्णय लिया, जिससे अधिक से अधिक जनजातीय कृषकों को फायदा होगा। इस के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रमुख कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिंडोरी, छिंदवाडा, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी एवं सिंगरौली के कृषकों से कोदो-कुटकी का उपार्जन किया जायेगा। साथ ही अन्य जिलों से मांग आने पर उन जिले के कृषकों से भी उपार्जन किये जाने पर विचार किया जायेगा।

श्री अन्न उत्पादक जिलों के कृषकों से श्रीअन्न कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (श्रीअन्न फेडरेशन) द्वारा कोदो-कुटकी का उपार्जन किया जायेगा। खरीफ 2025 में उत्पादित श्रीअन्न कुटकी 3500 रूपये प्रति क्विंटल एवं कोदो 2500 रुपये प्रति क्विंटल के मान से लगभग 30 हजार मेट्रिक टन का उपार्जन किया जायेगा। इसके लिए श्रीअन्न फेडरेशन को 80 करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋण शासन के मूल्य स्थिरीकरण कोष से प्रदाय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कृषको को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपये प्रति क्विंटल के मान से संबंधित कृषकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदाय किये जायेंगे।

किसानों को राहत राशि देने में कोई कमी नहीं करेंगे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

गत वर्ष की तुलना में तीन गुना राहत राशि का हुआ वितरण

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस साल अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसानों की फसल को नुकसान हुआ। पीला मोजैक और कीट प्रकोप ने भी किसानों को परेशानी में डाला। इसी तरह बारिश के कारण जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति से भी किसानों को पीड़ा हुई। ऐसे कठिन हालातों में सरकार ने किसानों को संबल देने में कोई कमी नहीं रखी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि अतिवृष्टि, बाढ़, कीट प्रकोप से फसल/ मकान क्षति की परेशानियों से जूझ रहे प्रदेश के 23 लाख 81 हजार से अधिक प्रभावित किसानों को अब तक लगभग 1802 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आरबीसी 6(4) के तहत दी गई इस राहत राशि से किसानों को फिर से खड़ा होने में बेहद मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राशि गत वित्त वर्ष 2024-25 में बांटी गई 660.57 करोड़ रुपए राहत राशि से करीब तीन गुना अधिक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अन्नदाता किसानों के लिए सरकार के खजाने में धन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के हर जरूरतमंद किसान को तत्परतापूर्वक सरकार का साथ, सहयोग और संबल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में 1590.74 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2022-23 में 726.15 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2023-24 में 758.62 करोड़ रुपए राहत राशि सरकार द्वारा वितरित की गई थी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि अतिवृष्टि /बाढ़ एवं पीला मोजैक/कीट व्याधि से फसल हानि के लिए 23 लाख 81 हजार 104 प्रभावित किसानों को 1623.51 करोड़ रुपए राहत राशि दी गई है। प्राकृतिक आपदा से हुई विभिन्न प्रकार की क्षतियों की पूर्ति के लिए राहत के रूप में 178.45 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इस प्रकार प्रदेश में अतिवृष्टि/बाढ़, पीला मोजैक/ कीट व्याधि से फसल हानि और विभिन्न प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को लगभग 1802 करोड़ रुपए की राहत राशि सरकार द्वारा वितरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि अतिवृष्टि हो या बाढ़, कीट व्याधि हो या कोई और प्राकृतिक आपदा, किसान हर मौसम में फसल नुकसानी का जोखिम उठाते हैं।

प्रदेश सरकार किसानों के जीवन को बेहतर करने के लिए कर रही है लगातार कार्य : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

आगर-मालवा एवं उज्जैन जिले के किसानों के लिए 403 करोड़ रुपये की राहत राशि की अंतरित

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं अन्य 29 लाख बहनों को 45 करोड़ रुपए सहायता राशि का वितरण

31 करोड़ के 30 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं सहित सभी के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार हैं। किसानों की जिंदगी बेहतर हो, इसके लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिये प्रदेश में अबतक 1800 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित की जा चुकी हैं। किसानों की फसलों को किसी भी कारण से क्षति होने पर सहायता दी जायेगी। किसान खून-पसीना एक कर कड़ी मेहनत से फसलें पैदा करता हैं। यदि प्राकृतिक कारणों से फसलों को क्षति होती हैं तो हमारा दायित्व है हम उनकी मदद करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन जिले की तराना तहसील में आयोजित राहत राशि वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए आगर-मालवा जिले के किसानो के लिए 138 करोड़ रुपये एवं उज्जैन जिले के किसानों के लिए 265 करोड रुपए इस प्रकार कुल 403 करोड़ रुपये की राहत राशि तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हितग्राहियों सहित गैर उज्ज्वला, विशेष पिछड़ी जनजाति की प्रदेश की कुल 29 लाख बहनों को 45 करोड़ रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदान की। समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लगभग 31 करोड़ रुपए के 30 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सोलर पम्प लगाने पर अब किसानों को केवल प्रोजेक्ट लागत की 10 प्रतिशत राशि ही देना होगी, शेष राशि सरकार द्वारा दी जायेगी। सोलर पम्प लगाने के बाद किसानों को बिजली बिल से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने बताया कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को दुग्ध उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। देशी गाय पालन पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहरीले रासायनिक खाद एवं दवाइयों की बजाय किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सम्मान निधि भी दी जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य हैं कि किसानों की आय बढ़े और वे आर्थिक रूप से मजबूत हों।

30 कार्यो का लोकार्पण एवं भूमि पूजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समारोह में 31 करोड़ रुपये लागत के 30 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इसमें 14 करोड़ रुपये के 21 कार्यों का लोकार्पण एवं लगभग 17 करोड़ रुपये लागत के 09 कार्यों का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि तराना को शाजापुर से जोड़ने के लिए नई सड़क बनेगी वही अब आगर रोड़ से तराना सीधे जुड़ेगा। प्रदेश मे अब अधिकतर सड़कें फोरलेन ही बन रही है। उन्होंने कहा कि कायथा में महाविद्यालय का भूमि-पूजन किया गया है, जिससे अब कायथा के विद्यार्थियों को महाविद्यालय की सुविधा मिलेगी। उन्होंने तराना में आईटीआई के लोकार्पण पर बधाई भी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि कनासिया-बरडंवा क्षेत्र में लगभग 08 हजार करोड़ रुपये लागत का कारखाना स्थापित हो रहा है, जिससे क्षेत्र के लगभग दो से तीन हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भावांतर भुगतान योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सोयाबीन का केन्द्र सरकार द्वारा 5328 रुपये मूल्य घोषित किया गया है। मंडी मे पंजीकृत किसानो द्वारा सोयाबीन विक्रय करने पर उन्हें मंडी मूल्य एवं घोषित मूल्य के अंतर की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।

सांसद श्री अनिल फिरोजिया एवं आगर-मालवा विधायक श्री माधव (मधु) गहलोत ने भी सबोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल, विधायक श्री अनिल जैन कालुहेडा, श्री सतीश मालवीय, श्री तेज बहादुर सिंह, डॉ. जितेंद्र पण्डया, शाजापुर विधायक श्री अरूण भीमावद, श्री राजेश धाकड़, श्री राजपाल सिसोदिया, श्री जयसिंह उमठ सहित जनप्रतिनिधि गण एवं गणमान्य नागरीक बडी सख्या में उपस्थित थे।

सहकारिता से समृद्धि की ओर : कुक्षी में दो दिवसीय सहकारी प्रदर्शनी रही आकर्षण का केंद्र

भोपाल | अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकारिता विभाग जिला धार एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित धार के सहयोग से जिला सहकारी संघ मर्यादित, धार द्वारा कृषि उपज मंडी प्रांगण कुक्षी में दो दिवसीय सहकारी प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया।

प्रदर्शनी का शुभारंभ किसान संगठन के जिला उपाध्यक्ष श्री रामेश्वर पाटीदार द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री एच.एस. जमरा (सचिव, कृषि उपज मंडी कुक्षी), श्री महेश पाटीदार (शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक), श्री बाबूलाल काग (पूर्व संचालक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक धार) सहित अनेक वरिष्ठ किसान, सहकारी कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा किसानों को मध्यप्रदेश शासन की 0% ब्याज दर ऋण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंदौर दुग्ध संघ की योजनाएँ, भावांतर भुगतान योजना तथा सहकारिता से संबंधित अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

मंडी सचिव श्री एच.एस. जमरा ने किसानों को भावांतर भुगतान योजना एवं उसके पंजीयन की प्रक्रिया के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान की।

इफको के क्षेत्र प्रबंधक श्री जितेंद्र राव ने नैनो यूरिया एवं डीएपी उर्वरक की नवीन तकनीक एवं लाभों पर चर्चा की।

सामाजिक कार्यकर्ता श्री विजय पाटीदार ने किसानों को शासन की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें अधिकाधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

प्रदर्शनी में जिला सहकारी संघ धार द्वारा पंपलेट, फ्लेक्स एवं प्रदर्शनों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया। साथ ही मनावर एवं कुक्षी तहसीलों में प्रचार वाहन रैली के माध्यम से सहकारिता विभाग की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शुभेन्द्र सिंह पवार एवं संघ के कर्मचारी श्री लक्ष्मीनारायण चावड़ा द्वारा किसानों को विभिन्न सहकारी योजनाओं, ऋण सुविधाओं एवं सदस्यता लाभों की जानकारी विस्तारपूर्वक दी गई।

दो दिवसीय इस प्रदर्शनी में किसानों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। कार्यक्रम ने सहकारिता आंदोलन के संदेश - **"सहकार से समृद्धि, सहयोग से विकास" - को सशक्त रूप में जन-जन तक पहुँचाया।**

कार्य पद्धति को बेहतर बनाने के लिए करें नवाचार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री ने लंबित प्रकरणों का समाधान करवाया ● जिस क्षेत्र में कोई शिकायत नहीं उन्हें करेंगे पुरस्कृत

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कार्य पद्धति को बेहतर बनाकर नए प्रयोगों और नवाचारों के माध्यम से नागरिकों के कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे करने के प्रयास किए जाएं। सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जिन जिलों अथवा क्षेत्रों में न्यूनतम शिकायतें होंगी, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में शिकायतें शून्य स्थिति में हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने कार्यों से अधिकारी-कर्मचारी सुशासन स्थापित करें। समाधान ऑनलाइन समीक्षा में प्रकरणों में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मियों को निलंबित करने

के साथ ही 19 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 5 शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने, 6 को कारण बताओ नोटिस देने, 7 प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही और एक प्रकरण में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

अच्छे कार्य करने वालों की सराहना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से वीसी द्वारा समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकों के लंबित प्रकरणों के समाधान की कार्यवाही करवाई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि आम लोगों के हित में प्रशासनिक अमला दक्षता से कार्य करे। बीते महीनों में हुए श्रेष्ठ कार्यों के लिए जिला स्तर पर रायसेन एवं दतिया जिले और विभाग स्तर पर ऊर्जा विभाग प्रथम स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चार अधिकारियों श्री के.के. दुबे उपनिरीक्षक थाना रावतपुरा जिला भिंड, श्री वेंकटेश नेरकर कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा मंडला, डॉ नंदिता निगम, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी धार और श्री कमलेश शुक्ला, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सतना को सितम्बर माह में सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायतों के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए उच्च प्रदर्शन के लिए बधाई दी। समाधान ऑनलाइन बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रमुख निर्देश

- नागरिकों के कार्यों में विलंब नहीं होना चाहिए। तत्परता से कार्य पूर्ण करें।
- शैक्षणिक परिसर में विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं मिलें, समय-समय पर कलेक्टर्स कैंपस में भ्रमण कर सुविधाओं का जायजा लें।
- प्रकरण में विलंब के लिए दोषी कर्मियों का दायित्व निर्धारित कर कार्रवाई करें।
- शासकीय विभागों के साथ बैंक के अधिकारी- कर्मचारी भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इनकी लापरवाही पर भी दण्डित करने की कार्यवाही की जाए।
- कार्यालयों में शिकायतें लंबित नहीं होना चाहिए।
- जनकल्याण के सभी प्रकल्पों को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए।
- राशन की दुकान स्थानांतरित करने के मामले में ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच और नगरीय क्षेत्र में पार्षद का सुझाव और सहमति ली जाना चाहिए।

(पहले पृष्ठ का शेष)

किसान हमारी अर्थव्यवस्था की हैं रीढ़ ...

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल सोयाबीन के लिए 2 लाख किसानों का पंजीयन हुआ था, भावांतर योजना दोबारा शुरू होने पर 9 लाख से अधिक सोयाबीन उत्पादक किसानों से पंजीयन करा लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनों को इसी भाई दूज से 250 रुपए अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी एवं पारदर्शिता लाकर डिलेवरी सिस्टम को और भी सरल बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली ही हमारे विकास का आधार है। जब अन्नदाता (किसान) खुश होता है, तो पूरी कायनात में खुशी छा जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार सोयाबीन की फसल को भावांतर योजना के दायरे में लाया गया है। पहले सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फ़सल बेचनी पड़ती थी, इससे उन्हें बहुत नुक्सान उठाना पड़ता था। सरकार ने ऐसे किसानों की पीड़ा समझी और सोयाबीन की फसल को भी हम भावांतर योजना में लेकर आये हैं। ऐसे किसानों को फसल के शासकीय खरीदी मूल्य और बाजार में बिक्री भाव में अन्तर की राशि की भरपाई अब हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसानों को उनकी फसल की उचित मूल्य की गारंटी लेंगे। भावांतर योजना के माध्यम से किसानों को उनके परिश्रम का पूरा मूल्य दिलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावान्तर योजना सिर्फ एक योजना नहीं है, यह सरकार और किसानों के बीच विश्वास का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि किसान का पसीना सूखने से पहले उसका हक़ उसके हाथ में पहुँचे।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए सदैव तत्पर है। किसानों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और मुआवजा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार फैसले लेती है। भावांतर योजना किसानों के लिए एक वरदान बनेगी।

विधायक एवं प्रदेशाध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण, उनकी उपज का उचित लाभ और किसानों को सम्मान निधि देने के लिए केन्द्र सरकार के साथ निरंतर समन्वय कर बेहतरीन कार्य कर रही है।

नर्मदापुरम सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में किसानों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। पहले किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देकर 2600 रुपए के भाव से गेहूं खरीदा। अब प्रदेश के सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना का लाभ दिया जा रहा है। राज्य सरकार पीले मोजेक से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा दे रही है। पशुपालक किसानों और गौमाता के कल्याण के लिए गौशालाओं को दिया जाने वाला अनुदान दोगुना कर 40 रुपए किया है। प्रदेश के किसानों को 12 हजार रुपए किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। किसान भाई विपक्ष के भ्रम में न आएं। सरकार ने मूंग की खरीदारी कर भी एक रिकॉर्ड कायम किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार हर सुख दुख में किसानों के साथ खड़ी है।

इस अवसर पर नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और विदिशा जिलों के लगभग 3 हजार से अधिक किसान उपस्थित थे। किसान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसानों को शासन की भावांतर भुगतान योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देना और किसानों को इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना था।

किसानों को दी गई भावांतर योजना की जानकारी

कृषि, सहकारिता और विपणन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना की प्रक्रिया, पंजीयन और तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (5328 रुपए प्रति क्विंटल) से फसल के बिक्री मूल्य के वास्तविक अंतर की राशि के लाभ वितरण की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। किसान सम्मेलन में बताया गया कि भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन उत्पादक किसान 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अपनी उपज कृषि उपज मंडियों में विक्रय कर सकेंगे। फ़सल बेचने के बाद भावांतर की राशि मात्र 15 दिनों के भीतर सीधे किसानों के आधार से लिंक बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भावांतर योजना के लिए किसानो द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर तक पूरी की जा चुकी है।

सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यसभा सदस्य श्रीमती माया नारोलिया, वरिष्ठ विधायक श्री सीताशरण शर्मा, विधायक श्री भगवान दास सबनानी, विधायक श्री प्रेमशंकर वर्मा, जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र यति, श्री महेन्द्र सिंह यादव, श्री हीरालाल पाटीदार, श्री मुकेश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में किसान बन्धु उपस्थित थे। सम्मेलन में किसान मोर्चा, किसान यूनियन, गौ-सेवक संगठन और राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ द्वारा मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर हल, गदा और बड़ी गजमाला से आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया गया।

माता गुजरी महिला कॉलेज में 'युवा संवाद' कार्यशाला का आयोजन

जबलपुर: ओरिएंटेशन कार्यक्रम के अंतर्गत माता गुजरी महिला कॉलेज में 'युवा संवाद' कार्यशाला का आयोजन किया गया।इस कार्यशाला का उद्देश्य नवप्रवेशी छात्राओं को उच्च शिक्षा के महत्व, आत्मविकास, करियर योजना, सहकारिता और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक करना था।कार्यक्रम में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, जबलपुर के प्राचार्य श्री विजय बर्वे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे।उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी देश की सबसे बड़ी ताकत है, और यदि वे सहकारिता, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास के सिद्धांतों को अपनाएँ, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है।उन्होंने सहकारिता को एक आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम बताते हुए छात्राओं को इसके क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

श्री यशोवर्धन पाठक ने उद्बोधन में कहा कि कॉलेज जीवन केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर है।उन्होंने छात्राओं को अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने और समाज के उत्थान में योगदान देने का संदेश दिया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने करियर विकास, डिजिटल साक्षरता, नैतिक मूल्यों और आत्मविश्वास निर्माण जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया।छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे और अपने अनुभव साझा किए।

एफपीओ सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल भोपाल में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं लेखापाल को मिला प्रबंधन, अनुपालन एवं डिजिटल प्रणाली का प्रशिक्षण

भोपाल: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा संचालित "किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्धन की योजना" के तहत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल ने दो दिवसीय "एफपीओ सुदृढ़ीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम" का आयोजन सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल में किया। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से एफपीओ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) और लेखापाल (Accountant) के लिए आयोजित किया गया, ताकि वे एफपीओ प्रबंधन, लेखा संधारण, वैधानिक अनुपालन, डिजिटल प्रणाली और बाजार संबद्धता के क्षेत्र में दक्ष बन सकें।

उद्घाटन और अतिथियों का उद्बोधन: कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की पूजा-अर्चना और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। उद्घाटन अवसर पर सहकारी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल के प्राचार्य श्री गणेश प्रसाद मांझी, श्री पी.के. एस. परिहार (पूर्व प्रबंधक, अपेक्स बैंक), श्री अरुण कुमार जोशी (भूतपूर्व प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल) और श्रीमती रेखा पिप्पल, लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

प्राचार्य श्री गणेश प्रसाद मांझी ने एफपीओ को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया और कहा कि संगठित किसान जब वैज्ञानिक प्रबंधन और बाजार आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो कृषि क्षेत्र में असीम संभावनाएँ खुलती हैं। श्री पी.के.एस. परिहार ने एफपीओ की आत्मनिर्भरता में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता की भूमिका पर जोर दिया। श्री अरुण कुमार जोशी ने सामूहिक नेतृत्व और सहयोग की भावना के महत्व को रेखांकित किया।

प्रथम दिवस की प्रमुख गतिविधियाँ: पहले दिन प्रशिक्षण सत्रों का संचालन श्री संतोष येडे (सोशल मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट), श्री सुभाष नंद तिवारी (कृषि एवं विपणन विशेषज्ञ), श्री रॉबिन सक्सेना (लेखा एवं विधि विशेषज्ञ) और डॉ. योगेश नामदेव (आईटी समन्वयक) द्वारा किया गया। प्रतिभागियों को निम्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई:

- बेसलाइन सर्वे और डेटा संकलन की प्रक्रिया
- एफपीओ प्रबंधन लागत और वैधानिक अनुपालन
- एम.आई.एस. (Management Information System) प्रणाली का प्रभावी उपयोग

प्रतिभागियों ने एफपीओ संचालन से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों को साझा किया और विशेषज्ञों से समाधान प्राप्त किए।

द्वितीय दिवस के तकनीकी सत्र:

दूसरे दिन विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने एफपीओ संचालन के व्यावहारिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रमुख सत्र और उनके विषय इस प्रकार रहे:

- **लेखा एवं रजिस्टर संधारण:** श्री रॉबिन सक्सेना (लेखा एवं विधि विशेषज्ञ) ने एफपीओ में रखे जाने वाले रजिस्टर और लेखा संधारण की प्रक्रिया समझाई तथा वित्तीय पारदर्शिता पर बल दिया।
- **e-NAM पंजीकरण और बाजार संबद्धता:** श्री नीरज जाट (एनसीडीईएक्स, इंदौर) ने राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने के लाभों पर विस्तार से जानकारी दी।
- **कार्यालय प्रबंधन एवं व्यय नियंत्रण:** श्री सुभाष नंद तिवारी (कृषि एवं विपणन विशेषज्ञ) ने कार्यालय स्थापना, प्रबंधन व्यय और क्रय प्रक्रिया के दिशा-निर्देश दिए।
- **भूमि संबंधी विषय** पर श्री प्रमोद रसेला ने एफपीओ के विस्तार हेतु शासकीय भूमि हेतु आवेदन की प्रक्रिया पर सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की गई।
- **संभावित व्यवसायिक गतिविधियाँ एवं उद्यम विकास:** डॉ. त्रिप्ती सिंह (वृंदा सोसायटी) ने मूल्य संवर्धन और व्यावसायिक अवसरों पर प्रस्तुति दी।
- **इक्विटी ग्रांट एवं वित्तीय सहयोग:** श्री गौरव जादोन (NCDC, भोपाल) ने सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहयोग से एफपीओ लाभान्वित होने की जानकारी दी।

समापन सत्र में श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, राज्य संघ भोपाल ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर श्री गौरव जादोन (NCDC, भोपाल), श्री संतोष येडे और डॉ. योगेश नामदेव भी उपस्थित रहे और उन्होंने प्रशिक्षण की उपयोगिता पर अपने विचार साझा किए तथा प्रतिभागियों से निरंतर सक्रिय रहने का आग्रह किया।

प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी, व्यवहारिक और मार्गदर्शक बताया। यह दो दिवसीय कार्यक्रम एफपीओ सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ, जिससे न केवल CEO और लेखापाल को प्रबंधन एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ, बल्कि सहकारिता की भावना को भी सुदृढ़ आधार मिला। राज्य सहकारी संघ भोपाल के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संगठित, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

हुनर को मिली नई दिशा - नौगांव सहकारी प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं को वितरित हुई टूल-किट्स

टूल-किट पाकर महिलाओं के खिले चेहरे, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव का किया धन्यवाद

नौगांव (छतरपुर)। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल एवं विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव में टूल-किट वितरण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार एवं स्वावलंबन की दिशा में सशक्त बनाना रहा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मानवेंद्र सिंह उर्फ भंवर राजा (पूर्व मंत्री, म.प्र. शासन एवं पूर्व विधायक) रहे। विशिष्ट अतिथियों में श्री अनूप तिवारी (नगर पालिका अध्यक्ष नौगांव), श्री मन्नूलाल रैकवार (प्रदेश सह-संयोजक मछुआ प्रकोष्ठ भाजपा एवं जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य) तथा श्री आशू मिश्रा (विधायक प्रतिनिधि नौगांव) उपस्थित रहे।कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव द्वारा फूल मालाओं एवं गुलदस्तों से किया गया।

मुख्य अतिथि का उद्बोधन

अपने संबोधन में माननीय श्री मानवेंद्र सिंह (भंवर राजा) ने कहा —"कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बूंद-बूंद से ही घड़ा भरता है। खेती-बाड़ी, सिलाई-कढ़ाई सभी आय के अतिरिक्त स्रोत हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल एवं विकास आयुक्त कार्यालय ग्वालियर की यह पहल सराहनीय है, जिससे नौगांव सहित प्रदेश की महिलाएं रोजगार से जुड़ रही हैं।"

नगर पालिका अध्यक्ष श्री अनूप तिवारी ने नगर पालिका की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

श्री मन्नूलाल रैकवार ने कहा कि —"हम सभी नगर की महिलाओं को आगे बढ़ाने, स्वावलंबी बनाने एवं शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।"

ग्वालियर से पधारे श्री अर्चित सहारे (सहायक निदेशक) ने सीएचसीडीएस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी दी, वहीं केंद्र के प्राचार्य श्री शिरीष पुरोहित ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ की गतिविधियों पर प्रकाश डाला।

श्री धर्मेन्द्र सिंह राजपूत (क्लस्टर समन्वयक, शीड संस्था भोपाल) ने हस्तशिल्प योजना से लाभान्वित होने की प्रक्रिया बताई। कार्यक्रम का संचालन श्री हृदेश कुमार (जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक) ने किया।

महिलाओं को वितरित की गई टूल-किट्स

कार्यक्रम के अंत में क्षेत्र की बड़ी संख्या में उपस्थित शिल्पकार महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई संबंधी टूल-किट वितरित की गई। टूल-किट पाकर महिलाओं के चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी और उन्होंने सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव के प्रति आभार व्यक्त किया।इस अवसर पर श्री अवतार सिंह राजपूत (शीड संस्था भोपाल), श्री बाबूलाल कुशवाहा (प्रशिक्षक, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव), पत्रकार कर्मयोगी संतोष गंगेले नौगांव, सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में शिल्पकार महिलाएं उपस्थित रहीं।

जूट क्राफ्ट कारीगरों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) के अंतर्गत 60 जूट क्राफ्ट टूलकिट्स का वितरण

भोपाल: हस्तशिल्प कारीगरों के कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (Comprehensive Handicrafts Cluster Development Scheme - CHCDS) के अंतर्गत भोपाल में जूट क्राफ्ट टूलकिट वितरण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।यह कार्यक्रम कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में तथा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के आयोजन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कुल 60 जूट क्राफ्ट कारीगरों को टूलकिट्स वितरित किए गए, जिससे उन्हें उत्पादन, गुणवत्ता सुधार और आय वृद्धि में सहायता मिलेगी। श्री नरसिंह सैनी, सहायक निदेशक, हस्तशिल्प सेवा केंद्र, भोपाल मुख्य अतिथि श्री सैनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि –"भारत की हस्तशिल्प परंपरा सदियों पुरानी है। आज भी यह हमारे ग्रामीण और पारंपरिक कारीगरों की पहचान है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य कारीगरों को केवल उपकरण देना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आधुनिक टूलकिट्स के उपयोग से न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक बाजार में हमारे जूट उत्पादों की पहचान भी मजबूत होगी।" उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ तभी पूर्ण रूप से संभव है जब कारीगर इन संसाधनों का प्रयोग नवाचार और गुणवत्ता सुधार के साथ करें। श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ने अपने संबोधन कहा –"राज्य सहकारी संघ का उद्देश्य कारीगरों को आर्थिक और तकनीकी दोनों स्तरों पर सशक्त बनाना है।

जूट क्राफ्ट सेक्टर में बड़ी संभावनाएँ हैं- यदि कारीगर अपने हुनर को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ें तो न केवल उनका जीवनस्तर सुधरेगा बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी।"उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण, विपणन सहायता एवं उपकरण वितरण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। श्री गणेश प्रसाद माझी, प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल ने कहा –"कारीगर हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। उन्हें आधुनिक युग के अनुरूप प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह पहल कारीगरों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगी।" उन्होंने यह भी बताया कि सहकारी प्रशिक्षण केंद्र लगातार ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से कारीगरों को प्रशिक्षित और सक्षम बनाने का कार्य कर रहा है।

श्री धर्मेंद्र राजपूत, सीड विशेषज्ञ संस्था ने अपने उद्बोधन में कहा –"कारीगरों को उपकरण मिलना केवल शुरुआत है; वास्तविक विकास तब होगा जब वे इन उपकरणों का उपयोग कर बाजार की मांग के अनुसार नवाचार करें। हमें 'वोकल फॉर लोकल' की भावना के साथ आगे बढ़ना है ताकि हमारे स्थानीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकें।"

कार्यक्रम में शामिल कारीगरों ने कहा कि उन्हें पहली बार इतने उपयोगी और आधुनिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इससे उनका कार्य तेज़ और सटीक होगा। कई कारीगरों ने बताया कि अब वे जूट उत्पादों के नए डिज़ाइन और विविध उत्पाद तैयार कर सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। यह कार्यक्रम हस्तशिल्प कारीगरों की आत्मनिर्भरता, कौशल संवर्धन और उत्पादन क्षमता वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। जूट क्राफ्ट टूलकिट वितरण से न केवल कारीगरों की उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नया उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।